Passenger traffic booked from and to this Railway Station is quite appreciable. This Flag Station caters to the need of travelling public of at least forty villages of that area. The Flag Station is not connected with any tar road. There is no bus transport service available from Khanpur Ahir to Rewari on Northern side, and from Khanpur Ahir to Harsahli on Southern side. The people of that area are incessantly demanding that Khanpur Ahir Flag Station should be upgraded as fullfledged railway station. I, in the interest of the general public of that area, urge upon the Railway Minister of the Union to upgrade Khanpur Ahir Flag Station to the category of fullfledged Railway Station.

(vii) Steps needed to Popularise the Kashmiri Handicrafts

SHRI ABDUL RASHID KABULI (Srinagar): Carpets, shawls and handicrafts of different types manufactured by skilled artisans of Kashmir Valley have great market all over the world besides having traditional markets in the country. These handicrafts, besides providing livelihood to lakhs of people, artisans, etc., in Kashmir in manufacturing, management and marketing, fetch rich dividends in the foreign markets. Unfortunately, the Central Government has not taken adequate steps for promoting, popularizing and sustaining the trade of Kashmiri handicrafts in the outside world. As a matter of fact, last year when slum in carpet and handicrafts industries affected their sale in foreign country, the Central Government of India did not do enough for its survival and lessening the crisis in the industry, causing extensive loss and unemployment. Since Government is earning a lot of foreign exchange in this sector, it must help the Jammu and Kashmir Government on a gigantic scale in promotion, sale and marketing of the handicrafts by earmarking sufficient funds for this and other purposes. Besides, it should on its own organise exhibitions of Kashmiri handicrafts and carpets in the European and Asian countries, including USA and USSR. The State of Jammu and Kashmir with meagre resources can do little in this direction which is primarily the responsibility of the Central Government.

(viii) Need to Control the price of tea by selling it through NAFED and NCCF throughout the country

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय. एक समय था जब चाय अमीरों के चोंचले के रूप में मानी जाती थी. किन्त आज वह झोंप-डियों तक की अनिवार्य चाह बन चकी है। कृतिम अभाव दिखाकर वस्तुओं के मृत्य बढ़ा देने का एक नया तरीका चल पड़ा है। गत वर्ष चाय का उत्पादन 5640 लाख किलो ग्राम था। इस वर्ष अभी तक 5500 लाख किलो ग्राम हो चुका है। गत वर्ष की अपेक्षा उत्पादन में कमी बहत आंशिक है किन्तु मृत्य बद्धि 100 प्रतिशत से ऊपर हो चुकी है। खेद है कि सरकारी संस्थानों ने भी अवसर का लाभ उठा कर इस मुल्य वृद्धि में सहयोग कर्के इस मुल्य वृद्धि के औचित्य पर ठप्पा लगा दिया है। गत 1978 79 वर्षों में भी इसी प्रकार चाय का उत्पादन 5570 लाख किलोग्राम से 5437 लाख किलोग्राम हुआथा किन्तु उस समय नेफेंड एवं एन० सी० सी० एफ० की संस्थाओं द्वारा समस्त देश में चाय एक निश्चित मुल्य पर बिकी करके मूल्यों पर का बूपा लिया गया था। अतः आज भी मैं आपके माध्यम से यह सुझाव सरकार को देना चाहती हं और आग्रह करती हं कि सरकार अविलम्ब इस प्रकार की व्यवस्था कर इस मृल्य वृद्धि को रोके और आम व्यक्ति को राहत पहंचाए।

(ix) Expansion of Durgapur Fertilizer

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): The machinery and plant installed in Durgapur Fertiliser Plant have become more or less obsolete. Reasonably, these outlived machinery and plants cannot produce any good results.

At present the country is facing acute shortage of fertiliser which is no doubt affecting the food production of our country severely. The country is forced to import fertiliser to make up the shortfall. As a result, a lot of foreign exchange is being spent on this account.

401

If the expansion of Durgapur Fertiliser Plant is considered, the infrastructure is readily available, which will minimise the cost of expansion project. The captive power plant of Durgapur Fertiliser Plant is nearing completion and the steady supply of power has been assured by the State Government. Hence there will be no problem in getting power which is required for the expansion of this project.

The employees of the Durgapur Fertiliser Plant had put up their best efforts to attain record production. This is being maintained over a period of six months in the hope that the expansion of Durgapur Fertiliser Plant which was assured by the Minister would come up soon.

In the circumstances, I would urge upon the Government for the expansion of Durgapur Fertiliser Plant immediately to meet the urgent requirements of fertiliser for augmentation of agricultural production of the country. I would like to mention here that the proposal for expansion of this Plant would be very much beneficial and judicious, technically and financially. I request that the Minister for Chemicals and Fertilisers should take steps to expedite its expansion programme.

(x) Irregular service of ships of S.C.I. Andaman-Nicobar Islands from to Calcutta and Madras

श्री बाब्राव परांजपे (जबलपुर): उपाध्यक्ष जी, अण्डमान द्वीप हवाई मार्ग से कलकत्ता तथा मद्रास से जुड़ा है तथा निकोबार एवं अन्य द्वीप अण्डमान से जुड़े हैं। सर्वसाधारण मनुष्य के लिए हवाई मार्ग बहुत खर्चीला है तथा इस कारण जल मार्गका उपयोग अधिक मात्रा में अण्डमान से कलकत्ता तथा मद्रास आने-जाने के लिए किया जाता है।

शिपिंग कार्पोशन ऑफ इण्डिया के स्वतः के जलयान कलकत्ता तथा अण्डमान के बीच आवा-गमन करते हैं तथा अण्डमान मद्रास मार्ग पर जलयान शिपिंग कार्पोरेशन के, परन्तु उसका प्रबन्ध किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में अनेकों

वर्षों से है। जलमार्ग के प्रवासी का आम मत यह है कि उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार किया जाना है जिस प्रकार किसी कैदी के साथ। अण्ड-मान का इतिहास सेल्युलर जेल में अंग्रेजों द्वारा रखे गये सैकड़ों क्रांतिकारियों के साथ जड़ा रहने के कारण अण्डमान के निवासी जल-मार्ग की गुलामी का अधिक अहसास करते हैं। जलयानों के आवागमन की अनियमितता इतनी अधिक है कि कलकत्ता-मदास में अनेकों दिन प्रवासी हेरा डालते हैं तथा अनिश्चय का शिकार होते हैं। इनमें से अधिकांश शासकीय कर्मचारी रहते हैं तथा भारत के सभी प्रदेशों से आते हैं। जलयानों की अव्यवस्था तथा अनियमितता का एक और दुष्परिणाम होता है कि अण्डमान द्वीप समह पर अनेको बार तमक, शक्कर, आलु, प्याज, माचिस आदि दैनदिन आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो जाता है। दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 को मैं तथा मेरे साथ अन्य दो लोक सभा सदस्यों ने इसका अनुभव अण्डमान में किया। फिर अण्डमान से जुड़े अन्य द्वीपों पर रहने वालों की दुर्दशा का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

अतएव गृह मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया की व्यवस्था में आमुलाग्र परिवर्तन लाने के आदेश प्रदान करें ताकि अनियमितता तथा अन्य परेशानियों से आम नागरिक को मुक्ति दिलायी जा सके।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): उपाध्यक्ष जी. मैं पहले कह चुका हूं और आज फिर कहना चाहता हं कि हमें जवाब तक नहीं मिलता है।

Already you have assured this House that the answer on the part of the Minister should be given to the Members.

एक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, जवाब भी नहीं दिया जाता। इसको पढने के बाद सिर्फ अपना नाम रेडियो और टी० बी० पर सून सकते हैं। अगर इसका यही परपज है तो इस नियम-377 के अधीन मैटर रेज करने का मामला खत्म किया जाए।